

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई 2018 — आषाढ 12, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई, 2018 (आषाढ 12, 1940)

क्रमांक-6833/वि. स./विधान/2018 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018) पुरःस्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराडे)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 12 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2018

वित्तीय वर्ष 2018-2019 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम. 1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्र. 3) अधिनियम, 2018 कहलाएगा.
- वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए राज्य की संचित निधि में से 48,77,54,02,967 रुपयों का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2018 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए चार हजार आठ सौ सतहत्तर करोड़ चौवन लाख दो हजार नौ सौ सड़सठ रुपये होता है उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.
- विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारत (3)	योग	
(1)	(2)	रुपये	रुपये	रुपये	
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	0	3,37,11,00,000	3,37,11,00,000
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	15,29,00,100	21,00,000	15,50,00,100
03	पुलिस	राजस्व	84,20,62,200	30,00,000	84,50,62,200
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	14,28,31,900	0	14,28,31,900
05	जेल	राजस्व	1,20,00,000	0	1,20,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	12,50,000	0	12,50,000

(1)	(2)	(3)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	8,50,30,000	0	8,50,30,000
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	1,800	0	1,800
10	वन	राजस्व	300	0	300
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	100	0	100
13	कृषि	राजस्व	60,00,00,000	0	60,00,00,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	8,42,00,000	0	8,42,00,000
17	सहकारिता	राजस्व	10,39,00,000	0	10,39,00,000
		पूंजी	5,00,00,100	0	5,00,00,100
18	श्रम	राजस्व	20,85,40,100	0	20,85,40,100
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	2,18,85,50,100	0	2,18,85,50,100
		पूंजी	28,50,000	0	28,50,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	100	52,58,067	52,58,167
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	1,22,54,00,200	0	1,22,54,00,200
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	49,46,00,000	0	49,46,00,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	20,50,00,000	0	20,50,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	3,14,40,52,100	0	3,14,40,52,100
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	30,00,000	0	30,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	31,30,00,100	0	31,30,00,100
		पूंजी	7,00,000	1,40,00,000	1,47,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	6,34,58,50,000	0	6,34,58,50,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000
33	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	3,84,00,00,000	0	3,84,00,00,000

(1)	(2)	(3)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	9,52,88,72,500	0	9,52,88,72,500
		पूंजी	2,15,38,00,300	0	2,15,38,00,300
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	300	0	300
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	100	0	100
46	विज्ञान और टेक्नालाजी	राजस्व	90,00,000	0	90,00,000
47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	राजस्व	12,00,04,000	0	12,00,04,000
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,50,000	0	4,50,000
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	राजस्व	100	0	100
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	44,44,51,100	0	44,44,51,100
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	3,28,25,03,400	0	3,28,25,03,400
		पूंजी	1,04,85,00,200	0	1,04,85,00,200
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	7,24,31,300	0	7,24,31,300
71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	5,00,00,000	0	5,00,00,000
		पूंजी	2,83,40,00,000	0	2,83,40,00,000
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी	400	0	400
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,82,11,300	0	2,82,11,300
		पूंजी	300	0	300
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	1,64,42,00,100	0	1,64,42,00,100

(1)	(2)	(3)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	4,10,78,00,300	0	4,10,78,00,300
	योग -	राजस्व	37,99,22,61,700	3,38,14,58,067	41,37,37,19,767
		पूंजी	7,38,76,83,200	1,40,00,000	7,40,16,83,200
	वृहद योग		45,37,99,44,900	3,39,54,58,067	48,77,54,02,967

उद्देश्य और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 2 जुलाई, 2018

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

“संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित”

चन्द्र शेखर गंगराडे
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.